NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA

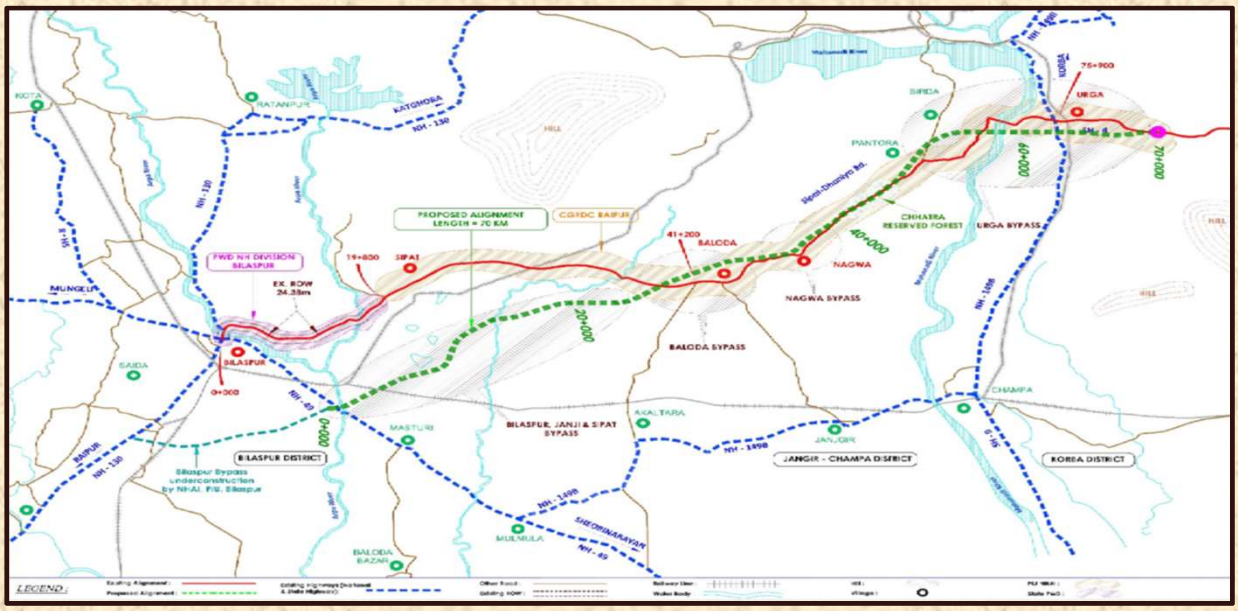

Bilaspur – Urga section of NH-130A

[Raipur – Dhanbad Economic Corridor]

Development of Economic Corridor to improve the efficiency of freight movement in India under Bharatmala Pariyojana

Total Length- 70.2 Km.

Draft Environmental Impact Assessment Report

Transys

DPR Consultant:-

Transys Consulting Pvt. Ltd.

FEEDBACK INFRA
Making Infrastructure Happen

Sub-Consultant:-

Feedback Infra Pvt. Ltd.

कार्यकारी सारांश

[हिंदी]

1 कार्यकारी सारांश

1.1 प्रस्तावना

भारत सरकार ने भरतमाला परिजोजन के तहत भारत में फ्राइट के बेहतर संचरण करने के लिए इकनोमिक कॉरिडोर , इंटर कॉरिडोर, फीडर रूट्स एवं नेशनल कॉरिडोर प्रस्तावित किया है।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्रस्तावित बिलासपुर - उरगा सेक्शन का नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है, जो की [राष्ट्रीय राजमार्ग 130 ए]- रायपुर धनबाद इकनोमिक कॉरिडोर [लॉट 3 / पैकेज -1] का एक हिस्सा है।

1.2 परियोजना का विवरण

प्रस्तावित परियोजना बिलासपुर बाईपास के अंत बिंदु से शुरू होती है, जो एन0एच0 -130 ए में निर्माणाधीन है। यह उरगा से 7.5 किमी की दूरी पर मौजूदा सड़क एस 0एच0 -04 के साथ समाप्त होता है।

यह रायपुर धनबाद इकनोमिक कॉरिडोर [लॉट 3/पैकेज -1] का एक हिस्सा है जिसकी कुल लंबाई 70.2 किलोमीटर है।

प्रस्तावित परियोजना छत्तीसगढ़ के तीन जिलों 'बिलासपुर, जनजगीर चंपा और कोरबा' से गुजरती है। परियोजना बिलासपुर, मस्तुरी, अकालता, बलोदा, कहगोरा, कार्तला, कोरबा एवं चितपाली तहसील से गुज़रती हैं।

प्रस्तावित राजमार्ग में लगभग 47 हेक्टेयर का वन क्षेत्र प्रभावित हो रहा है।

परियोजना के 10 किलोमीटर चरों तरफ कोई वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान या कोई अधिसूचित पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र नहीं है।

परियोजना के लिए लगभग 506.67 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाना प्रस्तावित है। अध्ययन क्षेत्र में लैंडयूज़ पैटर्न मुख्य रूप से कृषि योग्य है, इसके बाद बस्तियाँ, बंजर भूमि और वन क्षेत्र हैं।

स्थानीय लोगों, जानवरों को परेशानी रहित आवागमन के लिए एवं स्थानीय जल निकायों पर कोई प्रभाव न होने हेतु, 15 VUPs, 12 LVUP, 12 SVUP, 2 ROB, 3 फ्लाईओवर, 6 प्रमुख पुलों, 13 छोटे पुलों और 125 पुलियों को प्रस्तावित किया गया है ।

निर्माण के लिए पानी की कुल आवश्यकता लगभग 1508891 के०एल० है जिसकी पूर्ति टैंकर आपूर्ति या भूजल (यदि आवश्यक हो) से कि जाएगी ।

निर्माण की पूर्णता अवधि लगभग 24 महीने होने का अनुमान है। प्रस्तावित परियोजना का अनुमानित लागत INR 1181.92 करोड़ है।

1.3 पर्यावरण का विवरण

बेसलाइन डेटा 2018 के प्री मानसून सीजन के दौरान मार्च से मई, 2018 के दौरान एकत्र किया गया था। बेसलाइन डेटा ई आई ए रिपोर्ट के अध्याय 3 में प्रस्तुत किया गया है जो दिखाता है कि लगभग सभी मानकों के मूल्य निर्धारित सीमाओं के भीतर हैं।

1.4 अपेक्षित पर्यावरणीय प्रभाव और शमन के उपाय

- हीट आइलैंड प्रभाव के कारण क्षेत्र के सूक्ष्म जलवायु में थोड़ा बदलाव होने की अपेक्षा है।
- निर्माण गतिविधियों के दौरान पीएम के स्तर में मामूली वृद्धि होगी, जो निर्माण गतिविधियों खत्म होने के बाद फिर से निर्धारित सीमा के भीतर हो जाएगी ।
- सड़क के निर्माण के बाद ट्रैफिक डेंसिटी में वृद्धि के कारण इस क्षेत्र में शोर स्तर में मामूली वृद्धि का अनुभव होने की संभावना है।
- निर्माण सामग्री, तेल, तेल, ईंधन और पेंट इत्यादि के फैलाव के कारण जल निकायों के लिए प्रदूषण हो सकता है। यह उन स्थलों में अधिक प्रमुख होगा जहां परियोजना सड़क, नदियां, नहरों, नल्लाहों आदि को पार करती है। इसके लिए शमन के उपाय बनायेगये ह जो के इन जल निकायों को प्रदुषण से बचायेंगी।
- प्रस्तावित परियोजना के निर्माण के दौरान, परियोजनाओं के निर्माण के कारण स्थलाकृति मामूली रूप से बदल सकती है।

1.5 विकल्प का विश्लेषण

विकल्पों का विस्तृत विश्लेषण आयोजित किया गया है। सभी विकल्पों का तुलनात्मक विश्लेषण भी आयोजित किया गया है। सड़क के प्रस्तावित विकास से क्षेत्र के आर्थिक मूल्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि, कुछ पर्यावरण और सामाजिक मुद्दे हैं जिन्हें सतत विकास के लिए कम करने की आवश्यकता है।

प्रस्तावित परियोजना के लिए तीन विकल्पों का अध्ययन किया गया था जिनमें से पहला सबसे उपयुक्त पाया गया ।

1.6 पर्यावरण मॉनिटरिंग प्रोग्राम

प्रस्तावित परियोजना के संचालन के दौरान पर्यावरण की स्थिति का आकलन करने के लिए महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मानकों की नियमित निगरानी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आधारभूत स्थितियों की जानकारी, परियोजना के संचालन के कारण पर्यावरणीय परिस्थितियों में किसी भी गिरावट के संकेतक के रूप में

कार्य कर सकती है और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए समय पर उपयुक्त कमजोर कदम उठाए जा सकते हैं। निगरानी एवं शमन के उपाय प्रदूषण के नियंत्रण के रूप में महत्वपूर्ण है क्योंकि नियंत्रण उपायों की प्रभावकारिता केवल निगरानी द्वारा निर्धारित की जा सकती है।

पर्यावरण निगरानी कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए 2 करोड़ रुपये की कुल राशि निर्धारित की गयी हैं

1.7 परियोजना के लाभ

परियोजना के लाभ बहु गुना हैं। यह बिलासपुर और कोरबा एवं अन्य दूरस्थ क्षेत्रों के बीच यात्रा के समय को काफी हद तक कम कर देगा। बेहतर कनेक्टिविटी के अलावा, यह समर्पित परियोजना क्षेत्र में आने वाले गांवों / कस्बों की आर्थिक स्थिति को भी बढ़ावा देगा।

1.8 परियोजना के लाभ

1.9 पर्यावरण प्रबंधन योजना

प्रस्तावित उपायों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए परियोजना विशिष्ट पर्यावरणीय प्रबंधन योजना तैयार की गई है।

ईआईए रिपोर्ट में प्रस्तावित परियोजना प्रभाव और प्रबंधन योजना का सारांश दिया गया है।

पर्यावरणीय प्रबंधन योजना (ईएमपी) को निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए पर्यावरण और सामाजिक-आर्थिक पहलुओं पर विभिन्न नियामक आवश्यकताओं के ढांचे के भीतर डिजाइन किया गया है:

- वनस्पतियों और जीवों में अशांति को कम करने हेतु ।
- वायु, जल, मिट्टी और शोर प्रदूषण को रोकने एवं कम करने हेतु ।
- सामाजिक-आर्थिक विकास में बेहतरी हेतु ।

पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) में निम्नलिखित मुख्य घटक शामिल होंगे:

- संभावित प्रभाव (सकारात्मक या नकारात्मक), पर्यावरणीय शमन उपायों, कार्यान्वयन अनुसूची, और निगरानी योजनाओं को एकीकृत करने के लिए।
- परियोजना विकास के प्रत्येक चरण से जुड़े संभावित पर्यावरणीय प्रभावों और प्रस्तावित प्रबंधन का वर्णन करने के लिए।
- स्वीकार्य मानकों के स्तर के लिए पर्यावरणीय प्रभावों को नियंत्रित करने के लिए, निर्माण के दौरान समुदाय के संभावित प्रभाव को कम करने और परियोजना के बाद के परिचालन चरणों के दौरान संभावित जोखिमों के कार्यबल को कम करने के लिए।

1.10 निष्कर्ष

ईआईए अध्ययन और परियोजना के लिए किए गए सर्वेक्षणों के आधार पर, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ईआईए रिपोर्ट में बताए गए उपायों के पर्याप्त कार्यान्वयन से संभावित पर्यावरणीय प्रभावों को स्वीकार्य स्तर पर कम किया जा सकता है।

पर्यावरणीय बजट में सुझाए गए पर्यावरणीय शमन उपायों, और उनके संबंधित लागत को कवर करने के लिए परियोजना में पर्याप्त प्रावधान किए जाएंगे।

प्रस्तावित परियोजना सड़क दक्षता में सुधार करेगी और आर्थिक विकास लाएगी। वायु और शोर की गुणवत्ता के मामले में, परियोजना लोगों के संभावित जोखिम स्तरों में काफी सुधार लाएगी।